बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 34 ● नई दिल्ली ● बुधवार 12 नवम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

दिल्ली ब्लास्ट पर नया खुलासा : मसूद अजहर की बहन के संपर्क में थी शाहीन, मिला था भारत में महिला ब्रिगेड बनाने का टास्क

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के लाल किला के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है। हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई जैश की महिला विंग हेड डॉ. शाहीन को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए है। डॉ. शाहीन लखनऊ की रहने वाली है और गिरफ्तार किए गए आतंकी डॉ. मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड भी है। एक दिन पहले सोमवार को उसे फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि डॉ. शाहीन जैश-ए-मोहम्मद के हेड मसूद अजहर की बहन सहीदा अजहर के संपर्क में थी। जांच में यह भी पता चला है कि उसी के इशारे पर भारत में जैश के लिए आतंक की महिला ब्रिगेड तैयार कर रही थी।

Delhi Blast की गूँज से पूरी दुनिया दहली, मौतों पर तमाम देशों ने जताया दुख, भारत को दिया पूरे समर्थन का भरोसा

नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास सोमवार शाम हुए भीषण कार विस्फोट ने न केवल देश बल्कि विश्व समुदाय को भी झकझोर दिया है। इस घटना में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से अधिक घायल बताए जा रहे हैं। दुनिया जब एक ओर आतंकवाद के नये नये रूप को देख रही है तब सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि दिल्ली धमाके की जाँच से क्या निष्कर्ष सामने आता है। दिल्ली में धमाका किसने किया, क्यों किया और धमाके में किन चीजों का इस्तेमाल हुआ इन सब सवालों के जवाब दुनिया भी चाहती है। दूसरी ओर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अगुआ बन कर उभरे भारत की राष्ट्रीय राजधानी में हुई इस घटना के बाद दुनियाभर के नेता भारत के साथ सांत्वना और अपना समर्थन जताने में जुट गये हैं। अमेरिका ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि वह स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के ब्यूरो ने कहा, हम प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। वहीं दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को लाल किला और चांदनी चौक क्षेत्र से दूर रहने और स्थानीय मीडिया से अपडेट लेने की सलाह दी है। उधर, विस्फोट के बाद ब्रिटेन ने यात्रा संबंधी सलाह जारी की है जबकि

रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने 'एक्स' पर लिखा, लाल किले पर हुए विस्फोट से स्तब्ध हूँ। विश्वास है कि भारत की गहन जांच इस घटना के कारणों का खुलासा करेगी। उधर, इज़राइल के राजदूत रेवुवेन अजार ने इसे हृदयविदारक घटना बताते हुए बचावकर्मियों और सुरक्षा बलों के त्वरित प्रयासों की प्रशंसा की। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि वह इस घटना से स्तब्ध है और भारत के साथ एकजुटता व्यक्त करता है। चीन के प्रवक्ता लिन जियान ने बताया कि किसी चीनी नागरिक के हताहत होने की सूचना नहीं है। उधर, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल ने भी इस विस्फोट में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना जताई और भारत के साथ एकजुटता प्रकट की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके ने कहा, भारत के लोगों के साथ हम दुख की इस घड़ी में खड़े हैं। देखा जाये तो दिल्ली में यह विस्फोट उस समय हुआ है जब भारत जी-20 के बाद वैश्विक मंच पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है और पड़ोसी क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं। विस्फोट की प्रकृति भले ही अभी स्पष्ट न हो, लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक असर गहरा है। यह बताता है कि शांति के केंद्र में भी असुरक्षा का साया मौजूद है। वहीं अमेरिका, रूस, चीन, इज़राइल और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों द्वारा तुरंत प्रतिक्रिया देना यह दिखाता है कि भारत की सुरक्षा अब केवल घरेलू चिंता नहीं, बल्कि एक क्षेत्रीय और वैश्विक विषय है। साथ ही अमेरिका और रूस की प्रतिक्रियाएँ संकेत देती हैं कि भारत की आंतरिक घटनाएँ अब विश्व-राजनीति के निगरानी तंत्र में सीधे दर्ज होती हैं। बहरहाल, जहां दुनिया भर में दिल्ली की घटना पर दुख जताने के बयान जारी हो रहे हैं वहीं भूटान में महामहिम राजा ने थिम्पू के चांगलिमथांग स्टेडियम में हज़ारों भूटानी लोगों के साथ दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों के लिए प्रार्थना सभा का नेतृत्व किया।

जयराम रमेश ने की दिल्ली में ग्रैप पर अति-निर्भरता की आलोचना; सालभर प्रदूषण नियंत्रण की मांग

नई दिल्ली । दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद केंद्र सरकार की ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। इस बीच, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सरकार की इस योजना पर अति-निर्भरता को लेकर चिंता जताई और सालभर ठोस उत्सर्जन नियंत्रण कार्रवाई की जरूरत बताई।

रमेश ने कहा कि दिल्ली में हर साल सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण के हालात बिगड़ते हैं, लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया केवल आपातकालीन कदमों तक सीमित रह गई है। उन्होंने 'एक्स' पर लिखा दिल्ली में GRAP-III लागू किया गया है। 2014 से 2017 के बीच सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण संकट को देखते हुए इस योजना को मंजूरी दी थी। उम्मीद थी कि समय के साथ यह कम जरूरी होगी क्योंकि सालभर उत्सर्जन में कमी आएगी, लेकिन अब यह पूरी तरह 'रिएक्टिव' हो चुकी है। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार को संकट प्रबंधन के बजाय संकट से बचाव पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मौजूदा हालात जारी रहे, तो दिल्ली को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए अब भी अपने PM2.5 स्तर में 60फीसदी से अधिक की कमी लानी होगी। रमेश ने कहा दिल्ली को साफ हवा के लिए सख्त और बहु-क्षेत्रीय कदम उठाने होंगे। ये सिर्फ अक्तूबर-नवंबर तक सीमित नहीं होने चाहिए बल्कि सालभर चलने चाहिए।

Stage III में क्या हैं प्रतिबंध?

निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक

सड़कों की मैकेनिकल सफाई और पानी का छिड़काव अनिवार्य

अप्रमाणित ईंधन उपयोग करने वाले उद्योगों पर पाबंदी

आवश्यक सार्वजनिक परियोजनाओं (सड़क, रेल, एयरपोर्ट) को छूट

केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में GRAP के तीसरे चरण को लागू किया। रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को दिल्ली का एक्यूआई 362 था, जो मंगलवार सुबह 425 तक पहुंच गया। CAQM ने कहा कि स्थिर मौसम, ठंडी हवाएं और अस्थिर वायुमंडलीय स्थितियां इस प्रदूषण वृद्धि के मुख्य कारण हैं। आयोग ने अपने बयान में कहा दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता की मौजूदा स्थिति को देखते हुए GRAP के स्टेज-III के तहत सभी कदम तुरंत प्रभाव से लागू किए जा रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली को किया बरी, 18 साल बाद रिहाई का रास्ता साफ

नई दिल्ली । निठारी हत्याकांड के दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोली को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने कोली की क्यूरेटिव याचिका स्वीकार कर ली, जिसके बाद अब वह जेल से बाहर आ सकेंगे, क्योंकि बाकी सभी मामलों में वह पहले ही बरी हो चुके हैं। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने दिया, जिसने कोली की याचिका पर खुले कोर्ट में सुनवाई की थी। अदालत ने कोली की सजा को रद्द करते हुए कहा कि अगर वह किसी और मामले में वांछित नहीं हैं, तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। यह फैसला उन परिवारों और कानूनी हलकों के लिए अहम है, जो पिछले 18 वर्षों से इस मामले पर नजर रखे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि अभियोजन पक्ष सुरेंद्र कोली के खिलाफ ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश नहीं कर पाया। अदालत ने माना कि जांच के दौरान कई गंभीर प्रक्रियागत खामियां रहीं, जिसके चलते दोषसिद्धि बरकरार नहीं रखी जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि किसी व्यक्ति को सिर्फ परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर उम्रकैद या फांसी नहीं दी जा सकती, जब तक कि आरोप बिना किसी संदेह के साबित न हों। सुरेंद्र कोली 2006 के नोएडा निठारी कांड में मुख्य आरोपी थे। उस वक्त निठारी गांव में बच्चों के गायब होने और फिर उनके शवों के मिलने से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी। जांच एजेंसियों ने कोली और उनके नियोक्ता मोनिंदर सिंह पंधेर को गिरफ्तार किया था। कोली को कई मामलों में दोषी ठहराया गया और उन्हें फांसी की सजा भी सुनाई गई थी, जिसे बाद में उम्रकैद में बदल दिया गया। कोली ने अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अब

अदालत ने उन्हें बरी करते हुए कहा कि न्याय का उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि सच्चाई सामने लाना है। निठारी गांव में रहने वाले बच्चे वर्ष 2004 से लापता हो रहे थे। बच्चों के लापता होने की जानकारी उनके परिजन थाना सेक्टर-20 पुलिस से लेकर बड़े पुलिस अधिकारियों तक से कर रहे थे। लेकिन पुलिस गुमशुदगी लिखने के बजाए उन्हें दुत्कार कर भगा देती थी। गायब होने वाले बच्चों में अधिकतर लड़कियां थीं। पायल नाम की एक युवती भी निठारी की पानी की टंकी के पास से लापता हो गई। उसके पिता सेक्टर-19 में रह रहे नंदलाल ने डी-5 सेक्टर-31 कोठी के मालिक व जेसीबी के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर मोनिंदर सिंह पंधेर पर बेटी के अपहरण का शक जाहिर करते हुए पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई के बजाय नंदलाल को ही बेटी से देह व्यापार करने का आरोप लगाते हुए भगा दिया। इसके बाद उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश देकर सीओ स्तर के अधिकारी को प्रगति आख्या के साथ कोर्ट में बुलाया। इसके बाद उसी साल 15 दिसंबर को अधिकारियों ने कोठी मालिक मोनिंदर सिंह व नौकर सुरेन्द्र कोली से पूछताछ की लेकिन रात में ही दबाव के चलते उन्हें छोड़ दिया।

दिल्ली में आज से शुरू होगी भारत-नेपाल सीमा वार्ता; जेन जेड प्रदर्शन के बाद पहली बैठक

नई दिल्ली । भारत और नेपाल के बीच वार्षिक सीमा वार्ता 12 नवंबर से दिल्ली में शुरू होगी। यह बैठक तीन दिनों तक चलेगी और दोनों देशों के शीर्ष सुरक्षा बलों भारत के सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और नेपाल के आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रमुख इसमें शामिल होंगे। यह बैठक खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यह सितंबर में काठमांडू में हुए 'जेन जेड' प्रदर्शन के बाद दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच पहली उच्च स्तरीय वार्ता होगी। वार्ता में सीमा पार अपराधों पर रोक, रियल-टाइम खुफिया जानकारी साझा करने की प्रणाली और दोनों देशों के बीच समन्वित सीमा प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह बैठक सीमा पर शांति और सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम साबित होगी। भारत की ओर से इस बैठक का नेतृत्व एसएसबी के महानिदेशक संजय सिंगल करेंगे, जबकि नेपाल की ओर से एपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल (डूल) राजू आर्यल की टीम भाग लेगी। एसएसबी के बयान में कहा गया है कि इस चर्चा में सीमा पार अपराधों की संयुक्त रोकथाम के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने, वास्तविक समय में सूचना साझा करने के लिए तेज और अधिक कुशल चैनल स्थापित करने और भारत-नेपाल सीमा पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वित सीमा प्रबंधन प्रथाओं को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिए जाने की उम्मीद है। पिछली बार ऐसी वार्षिक बैठक नवंबर 2024 में काठमांडू में आयोजित की गई थी। एसएसबी भारत-नेपाल की 1,751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा की निगरानी करती है, जो बिना बाड़ की है। इसके अलावा यह बल 699 किलोमीटर लंबी भारत-भूटान सीमा की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी संभालता है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विस्फोट के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी, कहा- न्यायालय देश के नागरिकों के साथ खड़ा है

नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने यहां लाल किले के निकट हुए कार विस्फोट के पीड़ितों को मंगलवार को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शीर्ष अदालत कानून का शासन कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उच्चतम न्यायालय देश के नागरिकों के साथ खड़ा है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ''उच्चतम न्यायालय कानून के शासन को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे।'' प्रधान न्यायाधीश ने वरिष्ठ अधिवक्ता शरत एस जावली और जगदीश चंद्र गुप्ता को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित एक 'पूर्ण न्यायालय संदर्भ' (श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित औपचारिक बैठक) में यह टिप्पणी की। जावली और गुप्ता का हाल में निधन हो गया था। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर धीमी गति से चल रही एक कार में जोरदार विस्फोट होने से 12 लोगों की मौत हो गई और कई वाहन जलकर खाक हो गए।

हरियाणा के वकील की गिरफ्तारी मामला, सुनवाई आज; धर्मांतरण रोधी कानून के खिलाफ अपील पर विचार नहीं

नई दिल्ली । हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने वकील विक्रम सिंह को गिरफ्तार किया है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगी। उन्होंने हत्या के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि वह इस मामले में केवल एक सह-अभियुक्त का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। विक्रम की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा, इस मामले में तत्काल सुनवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि एक वकील को महज पेशेवर काम करने के कारण फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। दलीलों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस पर बुधवार को सुनवाई करेंगे। बता दें कि वकील के खिलाफ कार्रवाई से भड़के वकीलों के संघ ने विगत छह नवंबर को दिल्ली की जिला अदालतों में काम का बहिष्कार किया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में वकील विक्रम सिंह ने अपनी तत्काल रिहाई और गुरुग्राम की एसटीएफ की कथित अवैध कार्रवाइयों की न्यायिक जांच कराए जाने की मांग भी की है। जुलाई 2019 में दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रू में पंजीकृत कराने वाले विक्रम वर्तमान में हरियाणा की फरीदाबाद जेल में बंद हैं। उन्होंने हरियाणा और दिल्ली सरकारों के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस मुकदमे में पक्षकार बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों के धर्मांतरण रोधी कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। ये याचिकाएं उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के धर्मांतरण रोधी कानूनों के खिलाफ दायर की गई हैं। एक याचिकाकर्ता के वकील ने तुरंत सुनवाई करने और धर्मांतरण रोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग की है। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाएं दिसंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएंगी। इससे पहले धर्मांतरण रोधी कानून पर रोक की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर को विभिन्न राज्यों को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा था। पीठ ने तब राज्यों को उनके जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया था और इसके बाद याचिकाकर्ताओं को दो सप्ताह में अपना उत्तर दाखिल करने की अनुमति दी थी। इस मामले को छह सप्ताह के बाद सूचीबद्ध किया गया था। पीठ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक द्वारा बनाए गए धर्मांतरण रोधी कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

भागवत की नई दृष्टि और समरस भारत की परिकल्पना

ललित गर्ग ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रायः हिंदूवादी संगठन के रूप में देखा जाता रहा है, परंतु वस्तुतः यह केवल एक धार्मिक या सांप्रदायिक संगठन नहीं, बल्कि भारतीयता और राष्ट्रीयता की जीवंत चेतना का प्रतीक है। संघ की मूल प्रेरणा वसुधैव कुटुम्बकम के भाव से उपजी है, जो भारत की सनातन संस्कृति की आत्मा है। इसी दृष्टि का विस्तार संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत के हालिया बेंगलुरु वक्तव्य में परिलक्षित हुआ, जब उन्होंने खुले हृदय से कहा कि ईसाई और मुसलमान भी संघ में शामिल हो सकते हैं। यह कथन न केवल साहसिक है बल्कि यह नए भारत, विकसित भारत और संतुलित भारत की सोच का परिचायक भी है। संघ में मुस्लिम, ईसाई सहित किसी भी संप्रदाय के लोगों के स्वागत की भागवत के वक्तव्य की व्यापक चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन यह वक्तव्य संघ की व्यापक सोच का भी परिचायक है और उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। मोहन भागवत का यह वक्तव्य संघ की विचारधारा में निहित उस भारतीय दर्शन की पुनः पुष्टि करता है जिसमें धर्म का अर्थ संप्रदाय नहीं बल्कि जीवन-मूल्यों का समुच्चय है। संघ के लिए हिंदुत्व किसी धर्म विशेष का नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की वह पद्धति है जिसमें समरसता, सह-अस्तित्व, करुणा और राष्ट्रनिष्ठा के तत्व समाहित हैं। यही कारण है कि संघ की दृष्टि में हिंदुत्व का अर्थ भारतीयता है अर्थात् भारत की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, संवेदना और जीवनशैली से आत्मीय जुड़ाव। ऐसा नहीं है कि इसके पहले संघ में विभिन्न संप्रदायों के लोगों को आने की अनुमति नहीं थी, यह अनुमति पहले से है और सच तो यह है कि संघ कार्यक्रमों में विभिन्न संप्रदायों के लोग आते भी रहे हैं। इनमें मुस्लिम और ईसाई भी हैं। इस सबके बाद भी धारणा यह भी है कि संघ के कार्यक्रमों में केवल हिंदू संप्रदाय के लोग शामिल होते हैं। इस धारणा का कारण यह है कि हिंदू संप्रदाय को लेकर संघ की अपनी विशिष्ट धारणा और परिभाषा है। उसके अनुसार देश में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं, भले ही उनका संप्रदाय और उनकी उपासना पद्धति कुछ भी हो। संघ की ओर से बार-बार यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि इस देश में रहने वाले समस्त लोगों के पूर्वज हिंदू ही थे, इसलिए वह सभी को हिंदू के रूप में देखता, मानता और संबोधित करता है। आखिर इस अवधारणा में कठिनाई क्या है? संघ के दूसरे सरसंघचालक गुरुजी गोलवलकर ने कहा था, हिंदुत्व केवल धर्म नहीं, वह संस्कृति है, जीवन का एक दृष्टिकोण है। इसी सूत्र को आगे बढ़ाते हुए मोहन भागवत स्पष्ट करते हैं कि हिंदुत्व किसी जाति, भाषा, मजहब या सीमित परंपरा का नाम नहीं है। संघ यह मानता है कि भारत में रहने वाले सभी लोग, चाहे वे किसी भी पंथ या विश्वास से जुड़े हों, इस धरती के सांस्कृतिक उत्तराधिकारी हैं। इसीलिए वे भारतीय हैं और इस दृष्टि से हिंदू अर्थात् इस भूमि की सभ्यता के उत्तराधिकारी। संघ की दृष्टि में हिंदू शब्द धार्मिक पहचान से अधिक सांस्कृतिक अवधारणा है। यह भारतीय जीवन का पर्याय है, जो समानता, सहिष्णुता और एकात्मता में विश्वास करता है। यही भाव सर्वे भवन्तु सुखिनः और एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्ति जैसे मंत्रों में प्रतिध्वनित होता है। आज की राजनीति में समाज को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बांटने का जो विषवमन चल रहा है, उससे राष्ट्र की एकात्मता को गहरी चोट पहुंच रही है। संघ का उद्देश्य इस विभाजनकारी मानसिकता के प्रतिरोध में खड़ा होना है। मोहन भागवत का यह वक्तव्य इसी विघटन की प्रक्रिया का प्रतिवाद है, एक ऐसी पुकार जो समाज के हर वर्ग को यह विश्वास दिलाती है कि राष्ट्र की आत्मा किसी संकीर्ण धार्मिक पहचान में नहीं, बल्कि साझा सांस्कृतिक चेतना में निहित है। संघ के लिए राष्ट्र ही सर्वोच्च देवता है। इस राष्ट्रभक्ति के केंद्र में धर्मनिरपेक्षता नहीं बल्कि धर्मसम्मतता है अर्थात् ऐसी आस्था जो सभी मतों का सम्मान करती है। इसी भाव से प्रेरित होकर संघ अपने कार्यकर्ताओं को हिंदू समाज की सेवा के माध्यम से समग्र भारतीय समाज की एकता का लक्ष्य देता है। भागवत का यह संदेश उस भारत की परिकल्पना करता है जिसमें मतभेद तो हो सकते हैं, पर मनभेद नहीं। वे मानते हैं कि जो भी इस भूमि में जन्मा है, उसका पूर्वज कोई न कोई हिंदू ही रहा है, यह कथन ऐतिहासिक नहीं, सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि भारत की सभ्यता का मूल एक ही रहा है, जिसने विविध रूपों में विकसित होकर अनेक धर्मों और संप्रदायों को जन्म दिया। इस संदर्भ में भागवत का दृष्टिकोण गांधीजी की उस संकल्पना से मेल खाता है जिसमें उन्होंने कहा था- मेरा हिंदुत्व सबको समेटने वाला है, किसी को बाहर करने वाला नहीं। यही समावेशी भाव राष्ट्र की एकता का आधार बन सकता है। यदि संघ इस पर बल देता है कि उसका उद्देश्य हिंदुओं को संगठित करना है तो इसका अर्थ यही है कि वह सभी भारतीयों को संगठित करके एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना करता है। कठिनाई यह है कि उसके विरोधी यह प्रचारित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते कि वह तो केवल हिंदू समाज का संगठन है। चूंकि यह दुष्प्रचार बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि संघ के स्तर एवं अन्य स्तरों पर इन देश तोड़क स्थितियों एवं दुष्प्रचार का स्पष्टीकरण होता रहे। संघ को लेकर फैलायी जा रही यह भ्रांति एवं गुमराह पूर्ण स्थितियों का खुलासा होना जरूरी है कि संघ संप्रदाय विशेष के लोगों को एकजुट करने का कार्य कर रहा है। यदि यह मिथ्या धारणा दूर हो सके तो संघ का कार्य और अधिक आसान एवं सृजनात्मक हो जाएगा, लेकिन यह मानकर चला जाना चाहिए कि संघ के विरोधी उसके बारे में दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। जो भी हो, संघ प्रमुख ने यह कहकर एक तरह से अपने विरोधियों और आलोचकों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है कि उसके कार्यक्रमों में सभी संप्रदायों के लोग आ सकते हैं, लेकिन केवल भारत माता के पुत्र के रूप में। उनकी इस पहल का सकारात्मक उत्तर दिया जाना चाहिए, उसका व्यापक स्तर पर स्वागत भी होना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि कुछ लोग भारत को माता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। क्या यह किसी से छिपा है कि संकीर्ण राजनीतिक कारणों से भारत माता की जय कहने से बचा जाता है? पिछले दिनों इसी संकीर्ण दृष्टि के कारण वंदे मातरम् के विरोध में स्वर सुनाई दिए। इक्कीसवीं सदी का भारत केवल आर्थिक या तकनीकी महाशक्ति नहीं बनेगा, यदि उसके भीतर मानसिक और सांस्कृतिक एकता का सूत्र न हो। संघ इसी सूत्र को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। भागवत का संदेश भारत के बहुलतावाद और धार्मिक विविधता में निहित एकता को स्वीकार करता है। यह एक ऐसा आमंत्रण है जो हर नागरिक को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि भारतीयता हमारी साझा पहचान है, बाकी सब उपाधियाँ हैं। इस दिशा में संघ का दृष्टिकोण समरस समाज की रचना पर केंद्रित है? ऐसा समाज जहाँ मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी सभी अपने धर्म का पालन करते हुए भी राष्ट्र को अपनी मातृभूमि मानें और भारतीय संस्कृति के गौरव में जुड़ें। मोहन भागवत के बेंगलुरु वक्तव्य ने हिंदुत्व की परिभाषा को एक व्यापक और आधुनिक संदर्भ दिया है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि संघ का हिंदुत्व किसी के विरुद्ध नहीं, बल्कि सबके लिए है। यह विभाजन नहीं, समन्वय का सूत्र है। यही सच्ची भारतीयता है- जो विविधताओं में एकता को, विरोध में संवाद को और मतभेद में सह-अस्तित्व को स्वीकार करती है। संघ का यह दृष्टिकोण बताता है कि हिंदुत्व का अर्थ किसी पंथ का वर्चस्व नहीं, बल्कि उस जीवनदर्शन का पुनर्जागरण है जिसमें भारत की आत्मा बसती है। यही भाव राष्ट्र को अखंडता, शांति और विकास के पथ पर अग्रसर करेगा।

सम्पादकीय...

बिहार चुनाव...

बिहार के पहले चरण की बंपर वोटिंग (65फीसदी) को पक्ष व प्रतिपक्ष गठबंधन अपने-अपने हिस्से की जीत बता रहा है। एनडीए के प्रभाव क्षेत्र माने जाने वाले पहले चरण के मतदान में मतदाताओं के जबर्दस्त उत्साह को देखते हुए महागठबंधन की बांछें खिली हुई हैं, वे इस अप्रत्याशित वोट प्रतिशत को व्यवस्था परिवर्तनकारी वोटों में शुमार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भाजपा नीत गठबंधन इसे वोटरों का अपने पक्ष में कदमताल बता रहा है। भाजपा का दावा है कि इस दफे वह बड़ी संख्या में अप्रवासी बिहारियों को वोट डालने के लिए बिहार लाने में कामयाब रही है, इस कार्य में भाजपा व संघ के नेता पिछले साल भर से मेहनत कर रहे थे, वहीं इस दफे 'एसआईआर' के तहत भले ही 70 लाख वोटरों के नाम कट गए हों, पर मतदान के रोज महिला व युवा मतदाताओं के उत्साह अलग ही कहानी बयां कर रहे थे, महागठबंधन युवा वोटरों के कदमताल को अपने पक्ष में मान रहा है तो एनडीए गठबंधन का कहना है कि 'महिला वोटर खुल कर नीतीश के समर्थन में बाहर आई हैं।' एक रिपोर्ट में पहले चरण के मतदान में कड़ी टक्कर बताई है और एडवांटेज एनडीए बताया है, पर इसके आंकड़े भी बता रहे हैं कि महागठबंधन 2020 के मुकाबले इस बार इस पहले फेज में शानदार वापसी कर रहा है। यह भी इशारे मिल रहे हैं कि भाजपा व एनडीए के कई हैवीवेट नेताओं का चुनाव इस बार थोड़ा फंस गया है, जो नेतागण कड़ी टक्कर में फंस गए हैं वे हैं-रामकृपाल यादव, विजय सिन्हा, विजय चौधरी, संजय सरावगी, मंगल पांडेय। वहीं सम्राट चौधरी को उनके कई अपनों से ही भीतरघात का सामना करना पड़ रहा है। लालू यादव का 'एमवाई' (मुस्लिम-यादव) समीकरण इस चुनाव में पूरी तरह एकजुट दिखा, इन दोनों को मिला कर बिहार में इसके 33 फीसदी के आसपास वोट शेयर है, अगर तेजस्वी यादव अपने इस परंपरागत वोट बैंक में कुछ अन्य जातियों को जोड़ने में कामयाब रहते हैं तो इस बार के चुनाव में लालटेन की चमक विरोधियों की आंखें चौंधिया सकती है। पीके की जनसुराज को लेकर जितना शोर-शराबा था वह उस कदर वोट में तब्दील होता नहीं दिखा। बिहार चुनाव की पूर्व बेला में हरियाणा चुनाव में कथित वोट चोरी को लेकर राहुल के खुलासे ने युवा व 'जेनजी' पीढ़ी को बाकई आंदोलित किया, अब यह व्यवस्था विरोधी वोटों में कितना तब्दील हो शह-मात की सियासी बिसात पर पीएम मोदी को अपने हर प्यादे की उपयोगिता, आक्रामकता व उनकी सामयिकता का बखूबी अंदाजा है। सो, जैसे ही उन्हें लगा कि बिहार की चुनावी हवा कोई और पैंतरा बदल सकती है, उन्होंने झट से वहां की पूरी चुनावी कमान अपने हाथों में थाम ली। जो नीतीश कुमार भगवा रणनीति में धीरे-धीरे किनारे कर दिए गए थे, उन्हें मुख्य रंगमंच पर अवतरित कराया गया। जिन इलाकों में जहां बड़े-बड़े चमकदार भाजपा नेताओं के पोस्टर लगे थे, वहां रातों-रात नीतीश के पोस्टर लगा दिए गए। ललन को उनके मोकामा में दिए गए बयानों के लिए उन्हें प्रतिनायक साबित करने की होड़ मच गई। भाजपा ने इस नैरेटिव को भी सिरे से नकारने के प्रयास किए कि ऊंची जातियों के नेता ही उनकी स्वभाविक पसंद है। भाजपा को बखूबी इस बात का इल्म हो गया था कि खुद को एनडीए का सीएम फेस घोषित नहीं किए जाने से नीतीश बेतरह कुपित हैं, उन्होंने जाने-अनजाने जदयू कैडर में भी यह संदेशा दे दिया है कि 'अगर इस दफे राज्य में एनडीए बहुमत में आ भी जाएगा तो भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी', पीएम मोदी ने समय रहते इस बात को भांप लिया था और वे रातों-रात भाजपा को बिहार चुनाव में कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ रहा है, वह अपने गठबंधन साथियों की समय-असमय बेजा मांगों से भी परेशान है। सूत्रों की मानें तो पहले फेज के चुनाव से पहले जब भाजपा के एक बड़े नेता पटना में एक प्रेस कांफ्रेंस करने वाले थे तो उनके एक घटक दल के मुखिया उनसे पटना मिलने आ पहुंचे। उस नेता जी ने भाजपा के बड़े नेता से गुहार लगाई कि 'अब चूंकि चुनाव सिर पर है और उनका चुनाव फंड लगभग खत्म हो चुका है तो उन्हें प्रति निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाने के लिए एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाए।' इस पर बड़े नेता बेतरह भड़क गए बोले-'अब भी आपका ध्यान चुनाव बनाने की जगह, पैसा बनाने पर है, मैं आपको अपना सर्वे दिखाता हूं, आपके 6 में से 5 उम्मीदवार तो अभी ठीक से लड़ाई में भी नहीं आ पाए हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जाओ, गांव-गांव घूमो और पूरी तरह चुनाव में लग जाओ, अपने उम्मीदवारों से भी कहें कि वे और मेहनत करें, हमारे लिए इस बार एक-एक बिहार चुनाव में महागठबंधन की नजर लगातार लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के पासवान वोटरों पर टिकी है, महागठबंधन इसमें सेंट लगाना चाहता है। यही सोचकर दरभंगा में एक-दूसरे के खिलाफ रणनीतियां बनीं । कहते हैं महागठबंधन को अपने इस पहल का फौरी लाभ मिला, एक अनुमान के अनुसार पहले चरण के मतदान में अकेले दरभंगा में लगभग 35 फीसदी पासवान वोटरों ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के पक्ष में वोट किया। इस बार भाजपा ने चिराग पासवान की पार्टी के लिए 29 सीटें छोड़ी हैं, पर माना जाता है कि इस दफे के चुनाव में चिराग की पार्टी के लिए जीत की दहाई का आंकड़ा छू पाना कतई आसान नहीं होगा।

होमवर्क में आ रहे बदलाव से बढ़ेगी सीखने की भूख

पढ़ाई करते समय बच्चे अक्सर किसी टॉपिक को दोहरा कर सीखने की कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं कि रट-रट कर परीक्षा देने जाते हैं, जिसकी जितनी अच्छी रटने की शक्ति, उतना अच्छा वो उत्तर लिखता है और परिणाम के आधार पर बुद्धिमान बच्चा कहलाता है, पर गहराई से सोचें, क्या वह बच्चा वाकई में बुद्धिमान है? क्या सच में उसने कोई ऐसा ज्ञान अर्जित किया जो भविष्य में कभी उसके काम आएगा? जवाब है नहीं ! ऐसे बच्चों की रटने की क्षमता तो खूब अच्छी होती है, लेकिन वे जीवन के असल ज्ञान से वंचित रह जाते हैं और अपनी शिक्षा का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। शिक्षा का अर्थ है सीखना। स्कूल में पढ़ाई करने के पश्चात आपने ऐसा क्या सीखा जिसका उपयोग आप जीवन को सार्थक बनाने के लिए करते हैं, यही स्कूली शिक्षा का आधार है। इसलिए रटने से अच्छा है कि किसी बात को गहराई से समझें जिससे वो बात आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए। पहले स्कूलों में होमवर्क का मतलब होता था गणित के एक जैसे सवाल बार-बार हल करना या लंबा-लंबा निबंध लिखना, लेकिन अब यह बदल रहा है। पूरे भारत की कक्षाएं जब बदलते शिक्षण तौर-तरीकों के अनुसार खुद को ढाल रही हैं, तो 'होमवर्क' जैसे साधारण कार्य में भी धीरे-धीरे बदलाव आ रहा है। यह अब बोझिल काम न रह कर, बल्कि खोज, सहयोग और रचनात्मकता के लिए उपयोगी उपकरण बन गया है। शिक्षाविदों का कहना है कि 'होमवर्क', जो पहले रटने पर आधारित था, अब नीतिगत बदलावों, डिजिटल उपकरणों और नए शिक्षण तौर तरीकों से बदल रहा है। ये रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और छात्रों के कल्याण पर जोर देते हैं। इसका मकसद छात्रों को सिर्फ पढ़ाई के लिए मजबूर करना नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाना है। अब होमवर्क में सिर्फ याद करने की बजाय सोचने, समझने और नई चीजें बनाने पर जोर दिया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों को प्रोजेक्ट बनाना, ग्रुप में काम करना और नयी जानकारी पर खोज करने जैसे काम दिए जा रहे हैं। इससे बच्चे अपने खुद के तरीके से सीखते हैं। इससे उनकी सोचने की क्षमता भी बढ़ती है। इस संदर्भ में देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के जरिये स्कूली छात्रों के होमवर्क में आ रहा बदलाव स्वागत योग्य है, जिसमें रटने की बजाय सीखने पर ज्यादा जोर है। इस नीति में छात्रों पर शैक्षणिक बोझ कम करने तथा गतिविधि आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने की वकालत की गयी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) समेत कई राज्य बोर्डों ने शिक्षकों से ऐसे होमवर्क देने को कहा है, जिन्हें करने में बच्चों को खुशी हो और उनमें प्रयोग करने की गुंजाइश हो। ऐसे में, स्कूलों की कोशिश है कि छात्रों को होमवर्क में ही व्यस्त न रखा जाये। ज्यादातर स्कूल आज प्रोजेक्ट आधारित काम देने लगे हैं और बच्चों को सामुदायिक जुड़ाव वाली गतिविधियों में शामिल करने लगे हैं।

छात्रों के होमवर्क को आसान और दिलचस्प बनाया जा रहा है, ताकि वे केवल किताबी कीड़ा बनकर न रह जायें। जोर इस पर दिया जा रहा है कि छात्र चीजों के बारे में खुद से सोचने, समझने और उन्हें बनाने की कोशिश करें। इससे बच्चों की रचनात्मकता जागती है और उनमें सोचने की क्षमता बढ़ती है। दरअसल, छात्रों को मिल रहे भारी-भरकम होमवर्क से उनकी रचनात्मकता खत्म होने लगी थी और इसे लेकर देशभर में चिंता जताई जा रही थी। वर्ष 2018 की वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट में पाया गया था कि 74 प्रतिशत शहरी छात्रों को दैनिक होमवर्क मिलता है, जिसमें उनके तीन से चार घंटे का समय चला जाता है, जबकि सीखने के मोर्चे पर उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने भी शिक्षकों को एक खास तरह का होमवर्क दिया था, जिसमें उन्हें छात्रों के साथ स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के अभियान से जोड़ा गया था, ताकि 'मेक इन इंडिया' और 'वोकल फॉर लोकल' को प्रेरणा मिल सके। यह बच्चों में देशभक्ति की भावना के साथ व्यावहारिक सोच बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। अमेरिका में नेशनल पीटीए (राष्ट्रीय अभिभावक शिक्षक संघ) और नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा बनाया गया 10-मिनट नियम यह बताता है कि बच्चों को हर रात अपनी कक्षा के हिसाब से लगभग 10 मिनट 'होमवर्क' करना चाहिए। इसका मतलब है कि पहली कक्षा के बच्चों को 10 मिनट 'होमवर्क' करना चाहिए, जबकि बारहवीं क्लास के बच्चों को 120 मिनट तक 'होमवर्क' करना चाहिए। भारत में 'होमवर्क' की अवधारणा भले ही बदल गई हो, लेकिन असल में कई भारतीय छात्र अक्सर रोजाना 3-4 घंटे 'होमवर्क' करने में बिताते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 'होमवर्क' की अवधारणा में बदलाव का एक कारण राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 भी है, जो छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करने और गतिविधियां आधारित सीखने को बढ़ावा देने पर जोर देती है। कई राज्य बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने इसके बाद परिपत्र जारी कर शिक्षकों से ऐसे काम देने को कहा है जो 'मनोरंजक, प्रायोगिक और व्यावहारिक हों'। विशेषज्ञों का कहना है कि होमवर्क की अवधारणा में यह बदलाव आंशिक रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 से प्रेरित है। इस नीति में छात्रों पर शैक्षणिक बोझ कम करने और गतिविधि आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करने की वकालत की गई है। कई राज्य बोर्डों और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने शिक्षकों से ऐसे होमवर्क देने को कहा है, जिन्हें करने में बच्चों को खुशी महसूस हो और उनमें प्रयोग की गुंजाइश हो। बदलाव के तहत अब होमवर्क में लंबे पैराग्राफ याद करने या गणित के सवाल हल करने के लिए नहीं दिये जाते। सिर्फ याद की गयी बातें पूछने के बजाय होमवर्क में छात्रों से अवधारणाओं के क्यों और कैसे को समझने की अपेक्षा भी की जाती है। छात्रों को पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के बजाय प्रयोग, प्रोजेक्ट और नवाचार की चुनौतियों के माध्यम से सीखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। ये नये तरीके आलोचनात्मक सोच, विश्लेषण और जानकारी की व्याख्या जैसी क्षमताओं को बढ़ावा देते हैं, जो रटने की प्रवृत्ति से अक्सर दब जाती रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, सिर्फ याद की हुई बातें पूछने के बजाय अब 'होमवर्क' में छात्रों से अवधारणाओं के 'क्यों' और 'कैसे' को समझने की अपेक्षा की जाती है। छात्रों को पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के बजाय, प्रयोग, प्रोजेक्ट और नवाचार चुनौतियों के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कॉप-30 : क्या कुछ बदलेगा!

जलवायु परिवर्तन के प्रभाव काफी भयानक होते जा रहे हैं। पृथ्वी का तापमान हर दशक 0.27 डिग्री सेल्सियस की दर से बढ़ रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वातावरण को काफी क्षति होगी। मौसम में बदलाव जैसे अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, सूखा, बाढ़ और तूफान चरम स्थिति पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। वैज्ञानिक दक्षिणी महाद्वीप के आसपास समुद्री बर्फ के पिघलने को लेकर चिंतित हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन से प्राकृतिक आपदाएं लगातार बढ़ रही हैं। द लांसेट काउंटडाउन आन हैल्थ एंड क्लाइमेट चेंज 2025 की रिपोर्ट बताती है कि पिछले वर्ष जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि क्षेत्र में 66 फीसदी और निर्माण क्षेत्र में 20 फीसदी का नुकसान हुआ। यह रिपोर्ट इशारा करती है कि अत्यधिक गर्मी के कारण श्रम क्षमता में कमी के कारण 194 अरब डॉलर की संभावित आय का नुकसान हुआ। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट विश्व के 71 शैक्षणिक संस्थानों और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के 128 अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने तैयार की, जिसका कुशल नेतृत्व यूनिवर्सिटी कालेज लंदन ने किया। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य के बीच संबंधों का अब तक सबसे व्यापक आंकलन किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता और जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन की विफलता से लाखों लोगों की जिंदगियां, स्वास्थ्य और आजीविका खतरे में है। रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को मापने वाले 20 में से 12 संकेतक अब तक के सबसे उच्चतम स्तर तक जा पहुंचे हैं। रिपोर्ट बताती है कि साल 2020 से 2024 के बीच भारत में औसतन हर साल दस हजार मौतें जंगल की आग से उत्पन्न पीएम 2.5 प्रदूषण से जुड़ी थीं। चिंता की बात यह है कि यह वृद्धि 2003 से 2012 की तुलना में 28 फीसदी अधिक है, जो हमारी गंभीर चिंता का विषय होना चाहिए। द लांसेट रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित पीएम 2.5 प्रदूषण भारत में 2022 के दौरान 17 लाख मौतों का जिम्मेदार था। सड़क परिवहन में पैट्रोल के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण?से लगभग 2.69 लाख मौतें हुई हैं। राजधानी दिल्ली और देश के कई महानगर प्रदूषण की मार झेल रहे हैं और प्रदूषण की मार सबसे ज्यादा बच्चों पर पड़ रही है। जन्म के साथ ही बच्चों पर प्रदूषण की काली हवा के चलते शारीरिक ही नहीं मानसिक बीमारियां भी हावी हो रही हैं। प्रदूषण की मार बाहर ही नहीं घर के भीतर भी महसूस होने लगी है। ब्राजील के बेलेम शहर में आज से जलवायु परिवर्तन पर कॉप-30 शुरू हो गया है। 21 नवम्बर तक चलने वाले इस सम्मेलन में 200 देशों के 50 हजार से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। अब सवाल यह है कि क्या कॉप-30 के सार्थक परिणाम निकलेंगे या यह महज दुनियाभर के नेताओं का सैर सपाटा ही सिद्ध होगा। जलवायु सम्मेलन पहले भी होते रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बदला। इसके लिए ?जिम्मेदार हैं विकसित देश जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाए हुए?हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही इस सम्मेलन से किनारा करके बैठे हुए हैं। पेरिस जलवायु सम्मेलन को 10 साल बीत चुके हैं लेकिन पृथ्वी के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक घटाने के उद्देश्य में कोई सफलता हाथ नहीं लगी।

ईज़ ऑफ़ लिविंग तभी संभव है जब ईज़ ऑफ़ जस्टिस सुनिश्चित हो -भारत की न्यायिक क्रांति का नया अध्याय

वैश्विक स्तरपर किसी भी राष्ट्र की विकास यात्रा केवल आर्थिक सूचकांकों या बुनियादी ढाँचों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि वहां कानागरिक कितना सुरक्षित, समान अवसरों से संपन्न और न्याय प्राप्त करने में सक्षम है।भारतीय पीएम ने नई दिल्ली में 'कानूनी सहायता वितरण तंत्र को मजबूत करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन में जो बात कही,ईज़ ऑफ़लिविंग तभी संभव है,जब ईज़ ऑफ़ जस्टिस सुनिश्चित हो वह न केवल भारत की न्यायिक नीतियों का नारा है,बल्कि एक लोकतांत्रिक दर्शन का सार भी हैं।बता दें भारत दुनियाँ का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,भारत का संविधान प्रत्येक नागरिकको समानअधिकार और कानूनके तहत समान सुरक्षा की गारंटी देता है। फिर भी कई लोग अशिक्षा गरीबी प्राकृतिक आपदाओं अपराध या आर्थिक तंगी व अन्य बाधाओं के कारण कानूनीसेवाओं तक पहुंच पाने में असमर्थ हैं।विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 के तहत विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना समाज के हाशिए पर पड़े और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी।चूंकि यह अधिनियम 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ था, इसलिए इसके कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में इस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता हैं विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाने वाली निः शुल्क कानूनी सहायता और अन्य सेवाओं की उपलब्धता के क्रम में,इस दिन, देश भर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए जाते हैं। साथियों बात अगर हम ईज ऑफ जस्टिस का अर्थ गूढ़ विस्तृत भाषा में समझने की करें तो, यह केवल अदालतों की संख्या बढ़ाने या नए कानून बनाने से नहीं है, बल्कि यह उस सामाजिक और संस्थागत परिवर्तन से जुड़ा है जो हर नागरिक को यह भरोसा देता है कि न्याय उसके द्वार तक पहुँचेगा, न कि उसे न्याय तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यह विचार आज के 21वीं सदी के ग्लोबल डेमोक्रेसी फ्रेमवर्क में इसलिए और भी अहम है क्योंकि दुनिया भर में जस्टिस एक्सेसिबिलिटी और लीगल एम्पावरमेंट को सतत विकास (एसडीजी-16) के एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है।भारत की न्याय प्रणाली की यह नई दिशा ईज़ी ऑफ़ लिविंग के समानांतर खड़ी है,जहां सरकार नागरिकों के जीवन में सुगमता, पारदर्शिता और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक तंत्र में सुधार कर रही है, वहीं न्यायिक सुधार उसकी सबसे संवेदनशील कड़ी है। जैसे आर्थिक उदारीकरण ने उद्योगों को मुक्त किया था, वैसे ही न्यायिक सशक्तिकरण नागरिकों को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाता है।संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय न्याय आयोग की रिपोर्टें लगातार यह दर्शाती रही हैं कि किसी भी देश का 'ईज़ी ऑफ़ जस्टिस इंडेक्स उसके लोकतंत्र की गुणवत्ता का सबसे प्रामाणिक संकेतक होता है। भारत इस दिशा में डिजिटल जस्टिस , लीगल ऐड डिलीवरी मैकेनिज्म और जस्टिस एट डोरस्टेप जैसे अभियानों के माध्यम से एक ऐसे मॉडल का निर्माण कर रहा है जो न केवल विकासशील राष्ट्रों बल्कि विकसित देशों के लिए भी प्रेरक बन रहा है। साथियों बात अगर हम जब भारत स्वयं को एक विकसित देश के रूप में देखेगा,तब हमारी न्याय व्यवस्थाकैसी होनी चाहिए इसको समझने की करें तो,जब हम स्वयं को एक विकसित राष्ट्र कहेंगे,तो हमारा जस्टिस डिलिवरी सिस्टम कैसा होगा?वास्तव में भारत की विज़न 2047 की दृष्टि का सबसे मूल प्रश्न है। विकसित राष्ट्र केवल जीडीपी, तकनीकी प्रगति या वैश्विक प्रभाव से नहीं बनता; बल्कि वह तब विकसित कहलाता है जब उसका नागरिक भरोसे से कह सके कि उसे समय पर, निष्पक्ष और सुलभ न्याय मिलेगा।भारत के न्यायिक तंत्र की आज जो चुनौतियाँ हैं,लंबित मामलों का बोझ, जटिल प्रक्रिया, कमजोर कानूनी सहायता तंत्र, और डिजिटल असमानता उन्हें दूर किए बिना डेवलपड इंडिया की परिकल्पना अधूरी है। इसी पृष्ठभूमि में इज़ ऑफ़ जस्टिस का नारा एक नीतिगत क्रांति का संकेत देता है।पहला स्तंभ, न्याय का डिजिटलीकरण- सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक ई-कोर्ट परियोजना ने भारत की न्याय प्रणाली को तकनीकी रूप से नया स्वरूप दिया है। आज 18 करोड़ से अधिक केस रिकॉर्ड डिजिटाइज़ हो चुके हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की सुविधा ने दूरस्थ इलाकों के नागरिकों को न्यायिक प्रक्रिया से जोड़ा है। नेशनल जुडीशल डेटा ग्रिडविश्व का सबसे बड़ा केस- डेटा प्लेटफॉर्म है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की न्याय सुधार रिपोर्टों में मॉडल के रूप में उद्धृत किया जा चुका है।दूसरा स्तंभ-कानूनी सहायता का सार्वभौमिकरण-भारत का नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अब केवल गरीबों के लिए नहीं, बल्कि कमजोर वर्गों महिलाओं, श्रमिकों, दिव्यांगों, आदिवासियों और प्रवासी मजदूरों, तक कानूनी सहायता पहुंचाने का मिशन लेकर चल रहा है।भारतीय पीएम द्वारा इस तंत्र को लीगल ऐड डिलीवरी मैकेनिज्म के रूप में सुदृढ़ करने का आह्वान यह संकेत है कि न्याय अब एक सेवा है, विशेषाधिकार नहीं।तीसरा स्तंभ-पारदर्शी व जवाबदेह न्यायिक ढांचा-विकसित भारत में न्याय केवल कानूनी व्याख्या का विषय नहीं रहेगा, बल्कि यह नागरिक अनुभव का हिस्सा बनेगा। जैसे 'इज़ डूइंग बिजनेस ' ने व्यापारिक नीतियों को सरल बनाया, वैसे ही 'ईज़ ऑफ़ जस्टिस ' न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता, समयबद्धता और नागरिक संवाद को प्राथमिकता देगा।इसलिए भविष्य का डेवलपड इंडिया जस्टिस मॉडल ऐसा होगा जहाँ-एफआईआर से लेकर फैसले तक की प्रक्रिया पूरी तरह ट्रैक की जा सके, वकील, जज और पीड़ित एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संवाद कर सकें,और न्यायालयों में मानवीय संवेदना को कानूनी प्रक्रिया से ऊपर स्थान दिया जाए।यह वही परिवर्तन है जिसे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएँ ह्यूमन सेंट्रिक जस्टिस कहती हैं,जहाँ कानून केवल नियंत्रण का नहीं, बल्कि संरक्षण का माध्यम होता है। साथियों बात अगर हम कानूनी सहायता वितरण तंत्र की मजबूती ,लीगल सर्विसेज़ डे और न्यायिक व्यवस्था का नया सामाजिक मिशन को समझने की करें तो,भारत में हर वर्ष 9 नवंबर को 'लीगल सर्विसेज़ डे मनाया जाता है, जो 1987 के 'लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट ' की वर्षगांठ है। यह दिन इस बात की याद दिलाता है कि न्याय तक पहुंच प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, और राज्य की जिम्मेदारी है कि वह इस अधिकार को हर व्यक्ति तक पहुंचाए। भारतीय पीएम का यह कथन लीगल एड डिलिवरी मैकेनिज्म की मजबूती और लीगल सर्विसेज़ डे से जुड़ा कार्यक्रम, हमारी न्यायिक व्यवस्था को नई मजबूती देगा।वास्तव में भारत की सामाजिक न्याय यात्रा का घोषणापत्र है।भारत का लीगल एड मिशन–भारत में 15 लाख से अधिक लोगों को हर वर्ष मुफ्त कानूनी सहायता दी जाती है। 'टेली-लॉ' जैसी डिजिटल योजनाओं ने 15 हजार से अधिक पंचायतों तक कानूनी सलाह की पहुँच बनाई है। इन प्रयासों से भारत एक ऐसा मॉडल तैयार कर रहा है जिसे जस्टिस डिलीवरी एट लास्ट माइल कहा जा सकता है।ग्रामीण भारत में न्यायिक जागरूकता का विस्तार– पीएम के विज़न के अनुरूप अब न्याय केवल अदालतों तक सीमित नहीं रहेगा। पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर 'लीगल एड क्लीनिक' और 'न्याय सखी' जैसी पहलें ग्रामीण स्तर पर न्यायिक साक्षरता का विस्तार कर रही हैं। यह पहल संयुक्त राष्ट्र की एक्सेस टू जस्टिस फॉर आल नीति के अनुरूप है, जो कहती है कि न्याय तभी प्रभावी है जब वह स्थानीय स्तर पर सुलभ हो। साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से भारत की पहल को समझने की करें तो विश्व बैंक की 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का लीगल एम्पावरमेंट फ्रेमवर्कदक्षिण एशिया में सबसे उन्नत है।टेली-लॉ', ई- कोर्ट्स', 'ई-परिसंस और 'लीगल ऐड चाटबोट्स ' जैसी योजनाएँ वैश्विक न्यायिक सुधार एजेंडा में उदाहरण के रूप में शामिल की गई हैं।इस संदर्भ में, लीगल सर्विसेज़ डे केवल एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि यह उस दिशा में राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है जहाँ न्यायिक प्रक्रिया एक सामाजिक आंदोलन बन चुकी है। जब न्याय गरीब तक पहुँचता है, तब लोकतंत्र मजबूत होता है;जब न्याय सरल होता है, तब नागरिक जिम्मेदार बनता है; और जब न्याय समय पर होता है, तब राष्ट्र वास्तव में विकसित कहलाता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि न्याय की सहजता ही विकसित भारत की आत्मा,भारत की न्यायिक यात्रा अब पारंपरिक संरचना से आगे बढ़ चुकी है। ईज़ ऑफ लिविंग और ईज़ ऑफ़ जस्टिस अब एक ही सिक्के के दो पहलू है;जहाँ एक नागरिक के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है, वहीं दूसरा उसके अधिकारों की सुरक्षा करता है। प्रधानमंत्री के हालिया संबोधन ने यह स्पष्ट कर दिया है किन्यायिक सुधार अब केवल जजों या वकीलों का विषय नहीं रहा, बल्कि यह राष्ट्रीय विकास की रणनीति का केन्द्रीय अंग बन चुका है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कदम ऑफसेट प्रिन्टर्स, ए-9, सायं पोस्टलाइन्स एस्स. दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/08862)

खादी ग्रामोद्योग आत्मनिर्भर भारत की रीढ़ — दुर्गेश राय

पडरौना, कुशीनगर।

प्रधानमंत्री मोदी के 'वोकल फॉर लोकल' संकल्प को साकार कर रहा है खादी अभियान

जूनियर हाईस्कूल पडरौना में खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा आयोजित पंद्रह दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन मंगलवार को भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने किया।

उन्होंने कहा कि खादी ग्रामोद्योग आत्मनिर्भर भारत का अभिन्न अंग है, जिसने महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व तक एक नई पहचान बनाई है। दुर्गेश राय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में खादी ग्रामोद्योग विभाग हर घर स्वदेशी से हर घर आत्मनिर्भर की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। खादी के प्रसार से न केवल उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और कौशल विकास को भी बल मिला है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने स्वदेशी को आत्मनिर्भरता का प्राणस्वरूप माना था और आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यही खादी ग्रामोद्योग विभाग नवजीवन पा चुका है। विगत ग्यारह वर्षों में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर ग्रामीण भारत को आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त आधार प्रदान किया है।

कार्यक्रम का संचालन भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मनन्जय तिवारी ने किया तथा खादी ग्रामोद्योग सपहा के मंत्री पंकज पांडेय ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला महामंत्री सुदर्शन पाल, जिला उपाध्यक्ष दिवाकर मणि त्रिपाठी, जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल, जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद, आईटी संयोजक नमो नारायण मौर्य, पूर्व मंडल अध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता, कृष्ण बिहारी मिश्र, राम आधार चौहान, प्रमोद राय, शिव कुमार गोस्वामी आदि उपस्थित रहे।

प्रशिक्षु आरक्षियों को शस्त्र वितरण से पूर्व हुआ पारंपरिक शस्त्र पूजन

वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पुलिस अधीक्षक ने की पूजा-अर्चना, प्रशिक्षण के नए चरण की हुई शुरुआत

कुशीनगर।

रिजर्व पुलिस लाइन कुशीनगर में मंगलवार को प्रशिक्षु आरक्षियों को शस्त्र वितरण से पूर्व पारंपरिक शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने वैदिक मंत्रोच्चारण एवं पूजा-अर्चना के बीच शस्त्र पूजन संपन्न कराया। इस दौरान उन्होंने प्रशिक्षु आरक्षियों को संबोधित करते हुए कहा कि शस्त्र केवल बल का प्रतीक नहीं, बल्कि अनुशासन, निष्ठा और जनसेवा की भावना का प्रतीक है। प्रत्येक पुलिसकर्मी को इसका उपयोग केवल कानून व्यवस्था और जनहित में करना चाहिए। शस्त्र पूजन के साथ ही प्रशिक्षण का नया चरण प्रारंभ हुआ, जिसमें प्रशिक्षुओं को फील्ड ट्रेनिंग, शस्त्र संचालन, ड्रिल तथा परिस्थिति आधारित अभ्यासों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

दिल्ली ब्लास्ट के बाद देवरिया में हाई अलर्ट, डीआईजी ने किया रेलवे स्टेशन पर पैदल गश्त, सुरक्षा व्यवस्था की कसी कमर

देवरिया।

दिल्ली के लालकिला क्षेत्र में हुए धमाके के बाद पूर्वांचल में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए गोरखपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक एस. चन्नप्पा मंगलवार को देवरिया पहुंचे और जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण तथा रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था का स्वयं स्थलीय निरीक्षण किया। डीआईजी ने पुलिस लाइन सभागार में अपराध गोष्ठी कर जिले के पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी सूरत में अपराध और असामाजिक तत्वों को पनपने न दिया जाए। उन्होंने ऑपरेशन कन्विक्शन, गैंगस्टर एक्ट, साइबर अपराध, गो-तस्करी और शराब तस्करी से जुड़े मामलों में तत्काल और ठोस कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही, आगामी त्योहारों को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाने, बॉर्डर प्वाइंट्स पर चौकसी और हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने को कहा। डीआईजी चन्नप्पा ने निर्देश दिया कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत सभी थाना क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाए, और जहां कैमरे खराब हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त कराया जाए।

उन्होंने कहा कि थानेदार अपने क्षेत्रों में होटल, लॉज, ढाबों, बाजारों, स्कूलों और पेट्रोल पंपों की सुरक्षा का प्रतिदिन निरीक्षण करें, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। इसके बाद डीआईजी ने देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर पैदल गश्त कर सुरक्षा तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने प्लेटफॉर्म, यात्री प्रतीक्षालय, टिकट घर, आरक्षण काउंटर, पार्सल कार्यालय और पार्किंग क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की सतर्कता की जांच की।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था का बारीकी से परीक्षण किया। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यात्रियों की सुरक्षा हर कीमत पर सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। डीआईजी ने रेलवे सुरक्षा बल , रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के बीच संयुक्त गश्त एवं बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी संदिग्धों पर नजर रखेंगे और भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सतत निगरानी बनी रहेगी। चन्नप्पा ने अधिकारियों से कहा, पुलिस की मौजूदगी जनता के लिए विश्वास का प्रतीक होनी चाहिए, भय का नहीं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि स्टेशन परिसर में महिला सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और यातायात प्रबंधन को और मजबूत किया जाए। अंत में डीआईजी ने कहा कि देवरिया समेत पूरे गोरखपुर परिक्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां पूर्ण सतर्कता बरतें और किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई करें। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि सुरक्षा में चूक बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक और निरीक्षण के दौरान एसपी संजीव सुमन, एएसपी उत्तरी आनंद कुमार पांडेय, एएसपी दक्षिणी सुनील कुमार सिंह, सहित जिले के सभी सीओ, थाना प्रभारी और शाखा प्रभारी मौजूद रहे।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा और अधिकारों पर जागरूकता चौपाल

कुशीनगर । जिला प्रवेशन अधिकारी डी. सी. त्रिपाठी ने बताया कि महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति 5.0 के विशेष अभियान के तहत आज शत्रुधनजीत नरेन्द्र प्रताप गन्ना कृषक इंटर कॉलेज, नेबुआ नौरंगिया में जन जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हब फॉर इम्पावरमेंट ऑफ वूमेन टीम के जिला मिशन कोऑर्डिनेटर नलिन सिंह ने घरेलू हिंसा और दहेज उन्मूलन के दुष्प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की। वहीं, श्रीमती प्रीती सिंह, जेण्डर स्पेशलिस्ट ने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित सभी लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी। श्रीमती बन्दना कुशवाह, जेण्डर स्पेशलिस्ट ने प्रदेश में उपलब्ध सभी हेल्पलाइन नंबर जैसे 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 181 (वन स्टॉप सेंटर), 1090, 112, 108, 102 आदि के उपयोग और महत्व के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर पम्पलेट भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में कॉलेज प्राचार्य आर. सी. गुप्ता, आचार्य सुधीर कुमार सिंह, दिनेश कुमार गौतम, कपिल कुमार, सुजीत कुमार सिंह, नरेन्द्र मौर्या, श्रीमती पूजा यादव, श्रीमती रिता देवी सहित सैकड़ों छात्राएं और अन्य उपस्थित रहे। इस आयोजन का उद्देश्य छात्रों में महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और घरेलू हिंसा तथा दहेज प्रथा के खिलाफ समाज में सकारात्मक संदेश फैलाना था।

भटनी के उपनिरीक्षक मनोज उपाध्याय ने एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में चमकाया देश का नाम

भटनी देवरिया।

05 से 09 नवम्बर 2025 तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, चेन्नई में आयोजित 23वीं अन्तरराष्ट्रीय एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत उपनिरीक्षक मनोज कुमार उपाध्याय, कस्बा प्रभारी भटनी थाना, जिला देवरिया उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ाया।उपनिरीक्षक मनोज उपाध्याय का चयन आयु वर्ग 55+ हैमर थ्रो इवेंट के लिए हुआ था। इस प्रतियोगिता में 29 देशों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया।

उल्लेखनीय है कि उनके इवेंट में सभी 29 देशों के खिलाड़ी शामिल थे, जिनके बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में उन्होंने बेस्ट ऑफ 10 में जगह बनाकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की उपलब्धियों को मान्यता देते हुए मास्टर्स एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया व एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा एक विशेष आई.डी. कार्ड जारी किया गया है, जो आगामी वर्ष 2026 में सियोल दक्षिण कोरिया में प्रस्तावित विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में भागीदारी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। एशियन आयोग समिति के मानदंडों के अनुसार उपनिरीक्षक मनोज उपाध्याय को विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में खेलने का अवसर प्राप्त होगा। उनके इस उत्कृष्ट प्रदर्शन से न केवल देवरिया जनपद बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को भी गौरव की अनुभूति हुई है।

बेस्ट ऑफ 10 में बनाई जगह, अब सियोल में होने वाली विश्व चैम्पियनशिप में करेंगे प्रतिभाग

चार दिवसीय बंसराज सिंह स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ

कुशीनगर। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सखवनिया के प्रांगण में मंगलवार को चार दिवसीय बंसराज सिंह स्मारक फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ स्थानीय विधायक पी. एन. पाठक ने मार्च पास की सलामी लेकर और फुटबॉल को किक मारकर किया। प्रतियोगिता महात्मा गांधी इंटर कॉलेज और कन्या कस्तूरबा हाई स्कूल के संस्थापक बाबू बंसराज सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित की जा रही है। उद्घाटन मैच महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सखवनिया और टाउन क्लब तमकुही के बीच खेला गया। मध्यांतर तक दोनों टीमों ने गोल नहीं किया, लेकिन बाद में तमकुही की टीम ने बढ़त बनाई। विधायक पी. एन. पाठक ने कहा कि खिलाड़ी को खेल भावना के साथ खेलना चाहिए और अनुशासन ही किसी टीम को विजयी बनाता है। विद्यालय के प्रधानाचार्य अमर बहादुर ने आए हुए अतिथियों को माला पहनाकर और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। खेल सचिव नवनाथ दुबे ने खिलाड़ियों और सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया।

मैच में निर्णय की भूमिका हीरा प्रसाद गुप्ता, प्रभात मिश्रा और रहमतुल्लाह निभा रहे हैं, जबकि संचालन अंशुमान पांडे और विजय शुक्ला ने किया। इस अवसर पर आनंद मोहन सिंह, ज्ञान सिंह, समसुल हक, नेसार खान, फैयाज खान, महेश मिश्रा, आनंद लाल श्रीवास्तव, राजेश मिश्रा, शशिभूषण मिश्रा, विक्कू प्रसाद, पंकज श्रीवास्तव सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे।

दिल्ली पुलिस की जांच के 3 अहम मोर्चे, आतंकी साज़िश की खुल रही परतें

नई दिल्ली । दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सोमवार शाम लाल किला परिसर के पास हुए विस्फोट की अपनी जाँच को तीन अहम पहलुओं तक सीमित कर दिया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली पुलिस संदिग्ध की गतिविधियों, फरीदाबाद स्थित एक विश्वविद्यालय से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क और घटना में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित कर रही है। दिल्ली पुलिस की सबसे अहम जाँच उस महत्वपूर्ण तीन घंटे के इर्द-गिर्द घूम रही है जब डॉ. उमर, जो कथित तौर पर उस आई-20 कार को चला रहे थे जिसमें विस्फोट हुआ था, ने अपनी गाड़ी लाल किला पार्किंग क्षेत्र में खड़ी की थी। जाँचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि संदिग्ध, डॉ. उमर, दोपहर 3:19 बजे से शाम 6:22 बजे के बीच क्या कर रहा था, खासकर क्या वह गाड़ी के पास रुका था, किसी से मिला था, या हुंडई आइ20 के संबंध में इलाके की टोह ली थी। अधिकारी इस बात की भी जाँच कर रहे हैं कि क्या वह विस्फोट से पहले आस-पास की सड़कों पर भीड़ के जमा होने का इंतज़ार कर रहा था। सूत्रों के अनुसार, संदिग्ध दोपहर लगभग 3:19 बजे पार्किंग स्थल पर पहुँचा और शाम 6:22 बजे चला गया। पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि क्या उसने इस दौरान किसी से बातचीत की या किसी अन्य स्रोत से निर्देश प्राप्त किए। जाँचकर्ता यह भी पूछ रहे हैं कि उसने लगभग तीन घंटे तक उच्च-सुरक्षा क्षेत्र में क्यों रहना चुना। इस संभावना की भी जाँच की जा रही है कि वह किसी स्लीपर सेल से किसी सहायता या संकेत का इंतज़ार कर रहा था। जाँच का दूसरा पहलू फरीदाबाद के एक विश्वविद्यालय के डॉक्टरों के इर्द-गिर्द घूमता है, जिनके नाम जाँच के दौरान सामने आए हैं। पुलिस इस संदिग्ध नेटवर्क से जुड़े सक्रिय और निष्क्रिय सदस्यों की संख्या की जाँच कर रही है, जिसके स्लीपर सेल से जुड़े होने का अनुमान है। सूत्रों के अनुसार, अधिकारियों को संदेह है कि दिल्ली विस्फोट और फरीदाबाद में हुई बरामदगी राज्य की सीमाओं के पार सक्रिय एक बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है।

एजेंसियां बरामद हथियारों और विस्फोटकों के स्रोत, क्या वे अलग-अलग खेपों में आए थे, और उनकी डिलीवरी में किसने मदद की, इसकी भी जांच कर रही हैं।

Delhi blast : एक्शन में गृह मंत्रालय, NIA को सौंपी मामले की जांच

नई दिल्ली ।

पुलवामा से डॉ. उमर का दोस्त डॉ. सज्जाद गिरफ्तार ,भाई, मां-बाप हिरासत में; फरीदाबाद से अरेस्ट डॉ. शाहीन जैश महिला विंग की हेड

गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लाल किला विस्फोट मामले की जाँच आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दी है। सोमवार शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफ़िक सिग्नल पर एक धीमी गति से चलती कार में एक उच्च-तीव्रता वाला विस्फोट हुआ, जिसमें 12 लोग मारे गए और 25 से ज़्यादा घायल हो गए। प्रारंभिक फोरेंसिक जांच से पता चला है कि शक्तिशाली विस्फोट के लिए अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट के मामले में मंगलवार को यूएपीए के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की और राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर छापे मारे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, लाल किले के पास जिस कार में सोमवार शाम को विस्फोट हुआ उसके चालक का कथित तौर पर फरीदाबाद स्थित आतंकवादी मॉड्यूल से संबंध था। सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार शाम हुए विस्फोट के मद्देनजर आज एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस हमले में 12 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, आसूचना ब्यूरो (आईबी) के निदेशक तपन डेका, दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नलिन प्रभात डिजिटल माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत आतंकवादी हमला मामले की साजिश एवं ऐसे मामलों में सजा से संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की है। दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है और राष्ट्रीय राजधानी को 'हाई अलर्ट' पर रखा गया है तथा हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलवामा का निवासी और पेशे से चिकित्सक उमर मोहम्मद कथित तौर पर वह हुंदै आई20 कार चला रहा था, जो लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग क्षेत्र में हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुई थी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि लाल किले के पास जिस कार में विस्फोट हुआ उसे चला रहे व्यक्ति की पहली तस्वीर इलाके के सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। उन्होंने बताया कि व्यक्ति के फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से कथित तौर पर संबंध थे, जहां से विस्फोटक सामग्री का एक बड़ा जखीरा जब्त किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिलता है कि लाल किले के पास हुए विस्फोट में संभवत: अमोनियम नाइट्रेट, ईंधन तेल और डेटोनेटर का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस के एक सूत्र ने कहा कि प्रारंभिक जांच से दिल्ली विस्फोट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के बीच संभावित संबंध का संकेत मिलता है, जहां से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया गया था। सूत्र ने कहा, ''अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।

अमित शाह की ताबड़तोड़ बैठकें, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में हुए घातक विस्फोट के बाद स्थिति का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के एक और दौर की अध्यक्षता की, जिसमें एक दिन पहले आठ लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। बैठक दोपहर 3 बजे गृह मंत्रालय के कर्तव्य भवन स्थित कार्यालय में शुरू हुई। बैठक दो घंटे से अधिक के ब्रेक के बाद आयोजित की गई। बैठक का पहला दौर सुबह 11 बजे गृह मंत्री के आवास पर हुआ। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन, सूफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा ने भाग लिया। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। यह समीक्षा राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ी हुई सुरक्षा चिंताओं के बीच की गई है क्योंकि कई एजेंसियां लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट 1 और 4 के बीच एक ट्रैफिक सिग्नल के पास शाम 7 बजे के आसपास एक हुंडई आई 20 कार में हुए विस्फोट की जांच कर रही हैं। विस्फोट के तुरंत बाद, शाह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त और सूफिया ब्यूरो के निदेशक से बात की थी और एनआईए, एनएसजी, एफएसएल और दिल्ली पुलिस को शामिल करते हुए एक समन्वित, बहु-एजेंसी जांच का निर्देश दिया था।

सभी एजेंसियों को विस्फोट की प्रकृति और कारण की व्यापक जांच करने और जल्द से जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। पहले दौर की बैठकों के समापन के बाद, गृह मंत्रालय ने इसे एक संभावित आतंकवादी कृत्य मानते हुए मामले की जांच एनआईए को सौंप दी। यह निर्णय विस्फोट की प्रकृति और उससे जुड़े संबंधों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है। एनआईए दिल्ली पुलिस से औपचारिक रूप से जांच अपने हाथ में लेगी और मामले के सभी पहलुओं की जांच करेगी, जिसमें विस्फोट में प्रयुक्त सामग्री और संभावित आतंकी संबंध शामिल हैं। इससे पहले, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की एक विस्फोट-पश्चात जांच टीम ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (एफएसएल) की टीम के साथ मिलकर घटनास्थल से फोरेंसिक साक्ष्य एकत्र किए थे।

लाल किला विस्फोट : अखिलेश यादव ने पूछा, हमारी खुफिया जानकारी आखिर बार-बार क्यों विफल होती है?

लखनऊ।

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए विस्फोट को रोकने में खुफिया विफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया। इस विस्फोट में कम से कम 8 लोग मारे गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि राष्ट्रीय राजधानी में, खासकर उस इलाके के पास, जहाँ प्रधानमंत्री हर स्वतंत्रता दिवस पर अपना वार्षिक भाषण देते हैं, ऐसा विस्फोट कैसे हो सकता है। सपा प्रमुख ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि हमें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री और सरकार इस बात का खुलासा जरूर करेंगे कि इसके पीछे कौन है, जिसकी वजह से हमारी राजधानी, हमारे प्रतीक, जहाँ से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर भाषण देते हैं, इतनी बड़ी घटना घटी। हमारी खुफिया जानकारी हर बार क्यों विफल रही है? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के पास हुए हालिया विस्फोट पर अपनी संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और आश्वासन दिया कि सभी संबंधित एजेंसियां स्थिति को संभालने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। उन्होंने घायलों से मिलने के लिए अस्पताल जाने का भी जिक्र किया और उनके परिवारों के प्रति सरकार के सहयोग को दोहराया ताकि उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। दिल्ली पुलिस ने विस्फोट के सिलसिले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), विस्फोटक अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा, कोतवाली पुलिस स्टेशन में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16, 18 और विस्फोटक अधिनियम व बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ याचिका

नई दिल्ली ।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ द्रमुक, माकपा, पश्चिम बंगाल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस नेताओं की याचिकाओं पर निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एसआईआर कवायद को चुनौती देने वाली द्रमुक, कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई और तृणमूल कांग्रेस की अलग-अलग याचिकाओं पर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। शीर्ष अदालत बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण करने के निर्वाचन आयोग के फैसले की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले से ही सुनवाई कर रही है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की कवायद को 'सटीक' बताते हुए न्यायालय से 16 अक्टूबर को कहा था कि याचिकाकर्ता राजनीतिक दल और गैर सरकारी संगठन इस प्रक्रिया को केवल बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाकर संतुष्ट हैं। आयोग ने न्यायालय से यह भी कहा था कि अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद से नाम हटाने के खिलाफ किसी मतदाता ने एक भी अपील दायर नहीं की है। उसने याचिकाकर्ताओं के इस आरोप का खंडन किया था कि महीनों तक चली एसआईआर प्रक्रिया के बाद तैयार की गई राय की अंतिम मतदाता सूची में ''मुसलमानों को अनुपातहीन तरीके से बाहर'' किया गया। निर्वाचन आयोग ने 30 सितंबर को बिहार की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करते हुए कहा था कि इसमें मतदाताओं की कुल संख्या लगभग 47 लाख घटकर 7.42 करोड़ रह गई है जो निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले 7.89 करोड़ थी। अंतिम संख्या हालांकि एक अगस्त को जारी की गई मसौदा सूची में दर्ज 7.24 करोड़ मतदाताओं से 17.87 लाख अधिक है। मृत्यु, प्रवास और मतदाताओं के दोहराव सहित विभिन्न कारणों से 65 लाख मतदाताओं के नाम मूल सूची से हटा दिए गए थे। मसौदा सूची में 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए जबकि 3.66 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए जिससे कुल मतदाताओं की संख्या में 17.87 लाख की वृद्धि हुई है। बिहार में 243 सदस्यीय विधानसभा की 121 सीट पर पहले चरण का चुनाव बृहस्पतिवार को हो गया, जबकि शेष 122 निर्वाचन क्षेत्रों में 11 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी।

हेट स्पीच मामले में आजम खान को राहत

रामपुर । समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उन्हें हेट स्पीच (भड़काऊ भाषण) के मामले में बरी कर दिया है। आजम खान खुद कोर्ट में पेश हुए थे, जहां सिविल लाइंस कोतवाली में दर्ज इस केस में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान सपा के उम्मीदवार थे। उन्होंने 23 अप्रैल 2019 को सिविल लाइंस क्षेत्र में एक चुनावी सभा की थी। अगले दिन यानी 24 अप्रैल 2019 को तत्कालीन एसडीएम सदर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर प्रेम प्रकाश तिवारी ने आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज कराया था। कोर्ट से राहत मिलने के बाद आजम खान ने कहा, हमारा जीवन बेदाग है, यही हमारे जीवन का सच है। हम तमंचे बेचने वाले नहीं हैं। हमने गरीबों को घर दिए और जेलें काटी हैं।

दिल्ली धमाके पर कांग्रेस हमलावर, अजय राय बोले-

पुलवामा-पहलगाम जैसी निष्क्रियता, गृह मंत्री अमित शाह तुरंत इस्तीफा दें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली बम धमाकों के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी और उनके इस्तीफे की माँग की। राय ने एएनआई से कहा कि इस घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा? अमित शाह इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्हें तुरंत इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए। यह सरकार की नाकामी है। गृह मंत्री कल चुनावों में व्यस्त थे। कांग्रेस नेता ने पुलवामा और पहलगाम सहित पिछले आतंकवादी हमलों में केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर भी निशाना साधा। राय ने कहा कि वे दावा करते हैं कि कोई घुसपैठिया घुस नहीं रहा है, तो फिर घटनाएँ कैसे हो रही हैं। कुछ दिन पहले, पहलगाम में हमारे बच्चों की हत्या कर दी गई। वे देख रहे हैं कि क्या हुआ, फिर भी वे कहते रहते

दिल्ली ब्लास्ट पर भूटान से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया दो टूक मैसेज, षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा

भूटान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक कार विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त किया, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। भूटान की राजधानी थिम्पू की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दिल्ली में एक दुखद घटना घटी। मैं उन परिवारों का दर्द समझ सकता हूँ जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज मैं भारी मन से यहाँ आया हूँ। कल दिल्ली में हुई घटना ने सभी को झकझोर दिया है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि

विस्फोट के बाद से ही वह व्यक्तिगत रूप से स्थिति पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल रात मैं सभी संबंधित एजेंसियों के संपर्क में था। हमारी एजेंसियाँ इस विवाद की तह तक जाएँगी। सभी जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। सोमवार शाम ऐतिहासिक लाल किले के पास खड़ी एक कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट में 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। जाँच एजेंसियों ने हमले के कारणों और इसके पीछे के लोगों का पता लगाने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत बहु-एजेंसी जाँच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को दो दिवसीय यात्रा पर थिम्पू पहुँचे, जहाँ उनके भूटानी समकक्ष शेरिंग तोबगे ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य भारत-भूटान साझेदारी को गहरा करना और भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेषों की प्रदर्शनी के साथ मेल खाती है। वह थिम्पू के ताशीछोद्जोंग में पवित्र अवशेषों की पूजा भी करेंगे और भूटान की शाही सरकार द्वारा आयोजित वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भाग लेंगे।

महुआ हमारे नाम से जाना जाता है : तेज प्रताप को अपनी जीत का पूरा भरोसा, बोले- मैं ही नंबर 1

पटना। जनशक्ति जनता दल प्रमुख और महुआ सीट से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव ने महुआ निर्वाचन क्षेत्र से अपनी जीत का विश्वास व्यक्त किया है, जहाँ पहले चरण में मतदान हुआ था। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए, यादव ने कहा कि महुआ हमारे नाम से जाना जाता है और किसी के नाम से नहीं। मैं खुद को महुआ में नंबर 1 (महुआ सीट जीतकर) देखता हूँ। जनशक्ति जनता दल प्रमुख तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में थे। राष्ट्रीय जनता दल ने इस सीट से प्रेम कुमार को मैदान में उतारा था। तेज प्रताप इससे पहले 2015 में राजद उम्मीदवार के रूप में इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि 14 नवंबर को, जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होंगे, बिहार में बदलाव देखने को मिलेगा। तेज प्रताप यादव ने कहा, महिलाएँ बड़ी संख्या में मतदान कर रही हैं। (सरकार में) बदलाव होगा। 14 नवंबर को जनता हमें बताएगी कि किसने क्या विकास किया। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में दोपहर 1 बजे तक 47.62 प्रतिशत मतदान हुआ है। बिहार के 20 जिलों की 122 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान जारी है।

दिल्ली कार विस्फोट पर राजनाथ सिंह बोले, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा

नई दिल्ली ।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दिल्ली के लाल किले के पास हुए घातक कार विस्फोट पर गहरा दुख व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि इस दुखद घटना के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली रक्षा संवाद में बोलते हुए, सिंह ने सोमवार को हुए विस्फोट के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की, जिसमें 12 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। रक्षा मंत्री ने कहा कि सबसे पहले, मैं कल दिल्ली में हुई दुखद घटना में मारे गए सभी लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार हमले की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मैं अपने देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा, देश की प्रमुख जाँच एजेंसियाँ गहन जाँच कर रही हैं। रक्षा मंत्री ने नागरिकों को आश्वस्त किया कि जाँच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएँगे। सिंह ने जोर देकर कहा कि जिम्मेदार लोगों

को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। रक्षा मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब दिल्ली कार विस्फोट की जाँच में कई केंद्रीय एजेंसियाँ दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय कर रही हैं। जाँच ??जारी रहने के साथ, पुलिस सीसीटीवी फुटेज और डेटा विश्लेषण को महत्वपूर्ण सुराग के तौर पर देख रही है। जाँचकर्ताओं ने संदिग्ध वाहन की गतिविधियों का पता लगा लिया है और अब विस्फोट से पहले और बाद में स्थापित संभावित संचार संपर्कों की जाँच कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में विस्फोट से कुछ देर पहले संदिग्ध कार लाल किला पार्किंग क्षेत्र में प्रवेश करती और बाहर निकलती दिखाई दे रही है। फुटेज में चालक अकेला दिखाई दे रहा है। दरियागंज की ओर जाने वाले रास्ते की अब जाँच की जा रही है और आस-पास के टोल प्लाजा के फुटेज समेत 100 से ज्यादा सीसीटीवी क्लिप की जाँच की जा रही है ताकि वाहन की पूरी गतिविधि का पता लगाया जा सके। ऐतिहासिक लाल किला परिसर के पास हुए इस विस्फोट से इलाके में दहशत फैल गई और सुरक्षा व्यवस्था को व्यापक रूप से सक्रिय कर दिया गया।